इजरायल: सिफारिशें मिलीं, सरकार अभी दूर

समाचार की तिथि: 27 अक्टूबर से 7 नवंबर 2026
प्रकाशन तिथि: 2 नवंबर 2026
अद्यतन: 7 नवंबर 2026
समाचार की स्थिति 7 नवंबर 2026 तक है। राजनीतिक रुख और आगामी कार्यक्रम समाचार-रिपोर्टों से हैं। कनेसेट वेबसाइट का अंग्रेजी कानूनी अनुवाद स्वयं अनौपचारिक है और 15 अगस्त 2023 तक के संशोधन समेटता है; किसी भावी सरकार, निश्चित नामांकन या चुनाव की तारीख का दावा नहीं है।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

इजरायल में 27 अक्टूबर 2026 के चुनाव के बाद सरकार गठन का सवाल अनिर्णीत है। 30 अक्टूबर के प्रकाशित सीट-आँकड़ों के अनुसार 120 सदस्यीय कनेसेट में नेतन्याहू समर्थक गुट को 53, गादी आईजनकोट के विपक्षी गुट को 48 और अरब नेतृत्व वाले दलों को 19 सीटें मिली हैं। किसी एक मौजूदा गुट के पास 61 सीटें नहीं हैं।

3 नवंबर का नया घटनाक्रम: रिपोर्टों के अनुसार विपक्षी नेताओं ने सरकार बनाने के लिए बातचीत शुरू करने और राष्ट्रपति के समक्ष आईजनकोट की सिफारिश करने पर सहमति जताई। उसी दिन की अलग रिपोर्ट में घोषित समर्थन के आधार पर आईजनकोट के लिए 48 और नेतन्याहू के लिए 46 सिफारिशों का अनुमान था; यूनाइटेड तोरा जूडायज्म तथा अरब दलों का अंतिम रुख स्पष्ट नहीं था। ये परामर्श से पहले घोषित राजनीतिक रुख हैं, राष्ट्रपति का फैसला या गठित सरकार नहीं। 53 सीटों वाला चुनावी गुट और 46 अपेक्षित सिफारिशें अलग चीजें हैं।

2 नवंबर की रिपोर्ट में राष्ट्रपति कार्यालय के हवाले से परामर्श 4 और 5 नवंबर को निर्धारित बताए गए हैं। 3 नवंबर की स्थिति में उन्हें संपन्न नहीं माना गया है। केवल किसी दल की सिफारिश मिलने से उम्मीदवार प्रधानमंत्री नहीं बन जाता; आगे कानूनी प्रक्रिया और कनेसेट का विश्वास आवश्यक है।

4 नवंबर 2026 अद्यतन: आधिकारिक परिणाम राष्ट्रपति को सौंपे गए, परामर्श प्रक्रिया शुरू

4 नवंबर 2026 को केंद्रीय निर्वाचन समिति (CEC) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नोम सोलबर्ग ने 26वीं कनेसेट के आधिकारिक चुनाव परिणाम राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग को सौंप दिए। CEC ने परिणामों को मंजूरी देते हुए बताया कि मतदान की अखंडता से समझौते का कोई साक्ष्य नहीं मिला। रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रपति अब दलों के प्रतिनिधियों से सीटों के बढ़ते क्रम में परामर्श करेंगे और उस उम्मीदवार को सरकार बनाने का दायित्व देने की अपेक्षा है जिसे सबसे अधिक दलों की सिफारिश मिले।

परामर्श की पूर्व संध्या पर विपक्षी गुट का रुख स्पष्ट है: 3 नवंबर को हर्जलिया में हुई बैठक के बाद प्रमुख विपक्षी दल पूर्व सेना प्रमुख गादी आईजनकोट को प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन दे चुके हैं, हालांकि अरब नेतृत्व वाले दलों के समर्थन को लेकर गुट में मतभेद बना है। ऊपर बताए सीट-गणित (53-48-19) में अरब दलों का रुख निर्णायक बना हुआ है। यह अद्यतन प्रक्रिया की स्थिति है; सरकार गठन या किसी निश्चित नामांकन का दावा नहीं है।

5-7 नवंबर: आईजनकोट के लिए 67 सिफारिशें, लेकिन सरकार गठन अभी बाकी

घटनाक्रम: 5-7 नवंबर 2026 | अद्यतन प्रकाशन: 7 नवंबर 2026

5 नवंबर 2026 के परामर्श के बाद की रिपोर्टों के अनुसार 120 सदस्यीय कनेसेट के 67 निर्वाचित सदस्यों ने गादी आईजनकोट और 46 ने बेंजामिन नेतन्याहू को सरकार बनाने का अवसर देने की सिफारिश की। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने कहा कि दलों और गुटों के आपसी निषेध के कारण स्थिर सरकार की संभावना अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि वे रविवार (8 नवंबर) को निर्णय लेंगे और इस बीच कुछ दलों के नेताओं से व्यक्तिगत बातचीत करेंगे।

सिफारिश, सरकार नहीं: राष्ट्रपति के समक्ष किसी नाम की सिफारिश करना और उसी गठबंधन के साथ सरकार में शामिल होना अलग राजनीतिक निर्णय हैं। अधिक सिफारिशें मिलना अपने आप प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पूर्ण गठबंधन समझौते या कनेसेट के विश्वास-मत का प्रमाण नहीं है।

इसलिए पहले के 48 बनाम 46 अनुमान को 3 नवंबर की पूर्व-परामर्श स्थिति के रूप में पढ़ना चाहिए। 5 नवंबर की नई संख्या उसका अद्यतन है, चुनाव में मिली सीटों का नया परिणाम नहीं। 53-48-19 का चुनावी गुट-विभाजन और 67-46 की सिफारिशें अलग माप हैं। 5 नवंबर तक राष्ट्रपति ने अंतिम चयन नहीं किया था और सरकार का गठन भी नहीं हुआ था।

7 नवंबर तक की स्थिति

- यूनाइटेड तोरा जूडायज्म: इसके 7 सदस्यों ने किसी के नाम की सिफारिश नहीं की। निवर्तमान गठबंधन को चुनाव में 53 सीटें मिली थीं।
- गणित: आईजनकोट के चार प्रमुख दलों के पास 48 सीटें हैं। यूनाइटेड तोरा जूडायज्म को जोड़ने पर 55 और अरब दलों की 19 सीटें जोड़ने पर 67 होती हैं। बहुमत के लिए 61 चाहिए।
- बाहर से समर्थन: अरब दलों की सिफारिश का अर्थ सरकार में शामिल होना नहीं है। संयुक्त सूची ने बाहर से समर्थन की बात कही है।
- संभावित नया समीकरण: रिपोर्टों के अनुसार यिसरायल बेतेनू के नेता एविग्दोर लिबरमैन अति-रूढ़िवादी दलों के साथ बैठने को तैयार हो सकते हैं। यह रिपोर्ट है, तय समझौता नहीं।
- सैन्य सेवा की शर्त: आईजनकोट ने सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य, राष्ट्रीय या नागरिक सेवा को किसी भी सहयोगी के लिए शर्त बताया है। यह अति-रूढ़िवादी दलों के लिए संवेदनशील प्रश्न है।
- नई कनेसेट: 10 नवंबर को सदस्य शपथ लेंगे, जिसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा। राष्ट्रपति 8 नवंबर को दायित्व सौंपने का निर्णय बताएँगे। वे सिफारिशों की संख्या से बँधे नहीं हैं।

इस अद्यतन के स्रोत

- 5 नवंबर 2026: राष्ट्रपति के परामर्श और दलों की सिफारिशों की रिपोर्ट

- 6 नवंबर 2026: परामर्श के बाद सिफारिशें, यूनाइटेड तोरा जूडायज्म और स्पीकर का मुद्दा
- 7 नवंबर 2026: सिफारिशों का गणित, समय-रेखा और आईजनकोट की शर्तें

सीट-गणित और राजनीतिक सहमति का अंतर

गुट/दल	सीटें
नेतन्याहू समर्थक गुट: लिकुद 27, यूनाइटेड तोरा जूडायज्म 7, ओत्ज़मा येहूदित 7, शास 6, रिलीजियस जायनिज्म 6	53
विपक्षी गुट: याशार 21, बीयाखाद/टुगेदर 12, डेमोक्रेट्स 8, यिस्राइल बेतेनु 7	48
अरब नेतृत्व वाले दल: जॉइंट लिस्ट 11, राम 8	19

स्रोत-सीमा: यह विभाजन 30 अक्टूबर के प्रकाशित आँकड़ों पर आधारित है। सीटों को एक साथ जोड़ना गठबंधन समझौता हो जाने का प्रमाण नहीं है। विपक्ष और अरब दलों की सीटें मिलकर 67 होती हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए राजनीतिक सहमति भी चाहिए। 3 नवंबर की रिपोर्टों में अरब दलों के साथ साझेदारी पर विपक्षी नेताओं के बीच मतभेद कायम बताए गए हैं।

राष्ट्रपति किसे पहला अवसर दे सकते हैं?

बुनियादी कानून: सरकार की धारा 7 के अनुसार राष्ट्रपति संसदीय समूहों के प्रतिनिधियों से परामर्श के बाद किसी ऐसे कनेसेट सदस्य को सरकार बनाने का दायित्व देते हैं जो इसे स्वीकार करे। चुनाव परिणामों के आधिकारिक प्रकाशन से सात दिनों के भीतर यह दायित्व सौंपना होता है। सबसे बड़े दल का नेता होना अपने आप में पहला अवसर पाने का अधिकार नहीं है।

चुनावी सीटें, राष्ट्रपति के सामने सिफारिशें और विश्वास-मत में समर्थन तीन अलग चरण हैं।

सरकार गठन की चरणबद्ध प्रक्रिया

1. पहला दायित्व: आधिकारिक परिणाम-प्रकाशन से सात दिनों के भीतर, आवश्यक परामर्श के बाद दायित्व सौंपा जाता है। चुनाव वाले दिन या मीडिया की सीट-तालिका से यह घड़ी शुरू मान लेना गलत है।
2. पहला प्रयास: धारा 8 के तहत 28 दिन मिलते हैं। राष्ट्रपति विस्तार दे सकते हैं, लेकिन सभी विस्तार मिलाकर अधिकतम 14 अतिरिक्त दिन ही हो सकते हैं। विस्तार अपने आप नहीं मिलता।
3. पहली विफलता के बाद: धारा 9 के तहत राष्ट्रपति तीन दिनों के भीतर दूसरे इच्छुक सदस्य को अवसर देते हैं या कनेसेट अध्यक्ष को बताते हैं कि सरकार गठन की संभावना नहीं दिखती। दूसरे सदस्य को 28 दिन मिलते हैं; इस चरण में विस्तार का प्रावधान नहीं है।
4. कनेसेट सदस्यों का अवसर: दूसरी कोशिश विफल हो या राष्ट्रपति दूसरा दायित्व न दें, तो धारा 10 के अनुसार कुल सदस्यों का बहुमत, अर्थात कम-से-कम 61 सदस्य, 21 दिनों की अवधि में किसी सहमत सदस्य के पक्ष में लिखित अनुरोध कर सकता है। राष्ट्रपति दो दिनों के भीतर उसे दायित्व देते हैं। उस सदस्य को सरकार बनाने के लिए 14 दिन मिलते हैं। 21 दिनों की अनुरोध-अवधि और उम्मीदवार के 14 दिन अलग हैं।
5. अंतिम विफलता: धारा 11 की शर्तें लागू होने पर कनेसेट अपने कार्यकाल से पहले भंग मानी जाती है।

तारीख संबंधी सावधानी: आधिकारिक परिणाम-प्रकाशन की वास्तविक तारीख सत्यापित किए बिना 11 नवंबर को निश्चित अंतिम तिथि नहीं माना गया है। कानूनी समय-सीमा और आगामी कार्यक्रम को अलग रखें।

क्या सरकार बनाने के लिए हमेशा 61 पक्ष-मत चाहिए?

120 सदस्यीय सदन में 61 कुल सदस्यों का बहुमत है। लेकिन सामान्य सरकार गठन का विश्वास-मत और रचनात्मक अविश्वास-मत अलग नियमों से चलते हैं। बुनियादी कानून: सरकार की धारा 13(घ) के तहत सरकार अपना नीतिगत कार्यक्रम, संरचना और मंत्रियों के कार्य-विभाजन को सदन के सामने रखती है। कनेसेट के विश्वास व्यक्त करने पर सरकार गठित होती है।

बुनियादी कानून: कनेसेट की धारा 25 का सामान्य नियम मतदान में भाग लेने वालों का बहुमत है; मतदान से विरत सदस्यों की गणना नहीं होती। इसलिए 61 की संख्या कुल सदस्यों के बहुमत वाली शर्तों (जैसे धारा 10 और 28) से जुड़ी है, हर मतदान से नहीं।

इसके विपरीत धारा 28 का रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव कुल सदस्यों के बहुमत से किसी दूसरी सरकार में विश्वास व्यक्त करता है। केवल मौजूदा सरकार का विरोध करना पर्याप्त नहीं है। धारा 10 का 61 सदस्यों वाला अनुरोध भी प्रारंभिक विश्वास-मत का सामान्य नियम नहीं है।

कार्यवाहक सरकार और आगे के विकल्प

बुनियादी कानून: सरकार की धारा 30(ख) निकलती सरकार की निरंतरता बनाए रखती है, जब तक नई सरकार गठित न हो जाए। चुनावी गतिरोध अपने आप शासन को समाप्त नहीं करता। इस प्रावधान से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कार्यवाहक सरकार के हर संभावित निर्णय की वैधता पहले से तय है; किसी खास निर्णय पर लागू कानून और न्यायिक सीमाएँ अलग जाँच का विषय हैं।

राजनीतिक विकल्पों में दलों के बीच नए समझौते, बाहर से समर्थन वाली अल्पमत सरकार, व्यापक गठबंधन या निर्धारित प्रक्रिया विफल होने पर नए चुनाव शामिल हो सकते हैं। 3 नवंबर की रिपोर्टों के अनुसार अरब दलों के समर्थन तथा अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों के साथ समझौते पर राजनीतिक बाधाएँ बनी हुई थीं। किसी विकल्प को केवल अंकगणित के आधार पर निश्चित परिणाम नहीं बताया जा सकता।

गठबंधन की स्थिरता के प्रश्न

मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन-II: संसदीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष का विवेक उस लक्ष्य से जुड़ा है कि सरकार सदन का विश्वास प्राप्त करे। विविध प्रतिनिधित्व और सरकार की स्थिरता के बीच तनाव केवल सीटों से नहीं सुलझता; दलों की स्वीकार्य साझेदारी और नीति-सहमति भी जरूरी है। कानूनी समय-सीमाएँ गतिरोध को अनंत होने से रोकती हैं, लेकिन सहमति की जगह नहीं लेतीं।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. इजरायल में सरकार बनाने का पहला दायित्व देने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: सबसे बड़े दल के नेता को पहला अवसर देना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है।
कथन 2: राष्ट्रपति संसदीय समूहों के प्रतिनिधियों से परामर्श के बाद किसी सहमत कनेसेट सदस्य को दायित्व दे सकते हैं।
कथन 3: पहला दायित्व आधिकारिक चुनाव परिणामों के प्रकाशन से सात दिनों के भीतर दिया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

▼ उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)। धारा 7 में परामर्श, सदस्य की सहमति और परिणाम-प्रकाशन से सात दिनों की अवधि है। सबसे बड़े दल के नेता के लिए स्वतः अधिकार नहीं है।

प्रश्न 2. बुनियादी कानून: सरकार की धारा 10 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: संबंधित पूर्ववर्ती चरण विफल होने पर कम-से-कम 61 सदस्य किसी सहमत सदस्य के पक्ष में लिखित अनुरोध कर सकते हैं।

कथन 2: ऐसा अनुरोध करने के लिए 21 दिनों की अवधि है।
कथन 3: इस अनुरोध पर दायित्व पाने वाले सदस्य को सरकार बनाने के लिए 28 दिन मिलते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

▼ उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (b)। कथन 3 गलत है। धारा 10 के तहत राष्ट्रपति दो दिनों के भीतर दायित्व देते हैं और उम्मीदवार को 14 दिन मिलते हैं। अनुरोध के 21 दिन और सरकार बनाने के 14 दिन अलग हैं।

प्रश्न 3. इजरायल में विश्वास-मत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: प्रारंभिक विश्वास-मत के सामान्य नियम में पक्ष के मत विपक्ष से अधिक होना पर्याप्त है; हर स्थिति में 61 पक्ष-मत आवश्यक नहीं हैं।
कथन 2: रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव कुल कनेसेट सदस्यों के बहुमत से वैकल्पिक सरकार में विश्वास व्यक्त करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

▼ उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c)। प्रारंभिक सरकार गठन में धारा 13(घ) और कनेसेट की धारा 25 का सामान्य मतदान नियम लागू है। धारा 28 का रचनात्मक अविश्वास कुल सदस्यों का बहुमत और दूसरी सरकार में विश्वास चाहता है। दोनों प्रक्रियाएँ एक जैसी नहीं हैं।

आगे की राह

अगला निर्णायक बिंदु राष्ट्रपति के परामर्श और वास्तविक दायित्व-सौंपने का फैसला है। 4-5 नवंबर के परामर्श हो चुके हैं; राष्ट्रपति ने 8 नवंबर को निर्णय बताने की बात कही है। दायित्व मिलने के बाद संबंधित कानूनी घड़ी शुरू होगी। सिफारिश, गठबंधन में शामिल होना और विश्वास-मत में समर्थन देना अलग निर्णय हैं; इन्हें खबरों में अलग-अलग परखें।

स्रोत और सीमाएँ

- 30 अक्टूबर 2026: सीटों की तालिका
- 3 नवंबर 2026: विपक्षी बैठक और मतभेद
- 3 नवंबर 2026: परामर्श से पहले दलों की घोषणाएँ
- 2 नवंबर 2026: राष्ट्रपति कार्यालय के हवाले से परामर्श कार्यक्रम
- 4 नवंबर 2026: आधिकारिक परिणाम राष्ट्रपति को सौंपे गए, CEC की अखंडता-जांच
- 3 नवंबर 2026: विपक्षी नेताओं का आईजनकोट को समर्थन, अरब दलों पर मतभेद
- कनेसेट वेबसाइट: Basic Law: The Government, अंग्रेजी अनुवाद (15 अगस्त 2023 तक संशोधन)
- सरकारी वेबसाइट: Basic Law: The Knesset, धारा 25